



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 7 अप्रैल, 2005/17 चैत्र, 1927

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-171 004, 7 अप्रैल, 2005

संख्या वि० स० विधायन-गवर्नमेंट बिल/1-28/2005.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश वृत्तियों, व्यापारों,

आजीविकाओं और नियोजनों पर कर विधेयक, 2005 (2005 का विधेयक संख्या-12) जो आज दिनांक 7 अप्रैल, 2005 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

जे० आर० गाजटा,
सचिव,
हि० प्र० विधान सभा ।

2005 का विधेयक संख्यांक 12.

हिमाचल प्रदेश वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर विधेयक, 2005

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश राज्य में वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर के उद्ग्रहण और संग्रहण का उपबन्ध करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर अधिनियम, 2005 है ।

(2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जैसी राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

2. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा परिभाषाएं अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से हिमाचल प्रदेश वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर अधिनियम, 2005 अभिप्रेत है;

- (ख) "निर्धारण प्राधिकारी" से राज्य सरकार द्वारा धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन इस अधिनियम के अधीन कोई निर्धारण करने के लिए नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (ग) "आजीविका" में, किसी व्यक्ति की प्रायिक उपजीविका, व्यवसाय, कारबार या व्यापार सम्मिलित है ;
- (घ) "आयुक्त" से धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त आयुक्त अभिप्रेत है ;
- (ङ) "कम्पनी, निदेशक और शेयर धारक" के वही अर्थ होंगे जो उनके कम्पनी अधिनियम, 1956 में हैं; 1956
- (च) "उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त" से इस अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन आयुक्त की सहायता करने के लिए नियुक्त उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत संयुक्त/अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त भी हैं;
- (छ) "कर्मचारी" के अन्तर्गत —
- (i) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में, जिसे या तो भारत की या किसी राज्य की संचित निधि में से वेतन संदत्त किया जाता है ;
 - (ii) किसी निकाय, चाहे निगमित हो या न हो, जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन है जहां निकाय, राज्य के किसी भी भाग में क्रियाशील हो, चाहे इसका मुख्यालय राज्य के बाहर स्थित हो, की सेवा में;

- (iii) उपर्युक्त उप-खण्ड (i) और (ii) के अन्तर्गत न आए किसी नियोजक के किसी नियोजन में, वेतन या मजदूरी पर नियोजित कोई व्यक्ति है;
- (ज) "नियोजक" के अन्तर्गत, उसके अधीन नियमित आधार पर कोई वेतन या मजदूरी उपार्जित करने वाले किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में, ऐसे वेतन या मजदूरी के संवितरण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति या अधिकारी है और इसके अन्तर्गत नियोजक का प्रबन्धक या अभिकर्ता भी है ;
- (झ) "विनियुक्त" से किसी वृत्ति, व्यापार, आजीविका या नियोजन के सम्बन्ध में, ऐसी वृत्ति, व्यापार, आजीविका या नियोजन में पूर्णतः या अन्यथा आविष्ट कोई व्यक्ति अभिप्रेत है चाहे ऐसे व्यक्ति को कोई धनीय फायदा या कोई अन्य प्रकार का फायदा जो भी हो, वास्तविक रूप में प्रोद्भूत होता है या नहीं होता है ;
- (ञ) "सरकार या राज्य सरकार से" हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;
- (ट) "मास" से ग्रेगोरियन कलेंडर के अनुसार संगणित मास या उसका भाग अभिप्रेत है ;
- (ठ) "व्यक्ति" से हिमाचल प्रदेश राज्य में किसी वृत्ति, व्यापार, आजीविका या नियोजन में सक्रिय रूप से अन्यथा विनियुक्त कोई व्यक्ति, संगम या व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कोई हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब या संयुक्त कुटुम्ब, कोई फर्म, कोई कम्पनी चाहे निगमित हो या न हो, कोई सहकारी

सोसाइटी, कोई न्यास, कोई क्लब, कोई संस्थान, कोई अभिकरण, कोई निगम, कोई स्थानीय प्राधिकरण और केन्द्रीय या राज्य सरकारों का कोई विभाग है परन्तु आकस्मिक आधार पर मजदूरी उपार्जित करने वाला व्यक्ति इसके अन्तर्गत नहीं है ;

(ड) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ढ) "वेतन या मजदूरी" से किसी निर्धारित द्वारा, नियमित आधार पर प्राप्त वेतन या मजदूरी, मंहगाई भत्ता और समस्त अन्य पारिश्रमिक, चाहे नकदी या वस्तु के रूप में संदेय हो, और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 में यथा परिभाषित वेतन के बदले प्राप्त परिलब्धियां और लाभ अभिप्रेत है परन्तु बोनस (किसी भी रूप में या किसी भी कारण) या उपदान इसमें सम्मिलित नहीं है;

(ण) "अनुसूची" से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ;

(त) "राज्य" से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है ;

(थ) "कर" से इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन उद्गृहीत वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर अभिप्रेत है ;

(द) "व्यापार" से लाभ उपार्जित करने हेतु चलाया गया कोई कारबार अभिप्रेत है चाहे इससे कोई लाभ हुआ हो या न हुआ हो ; और

(ध) "वर्ष" से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है ।

अध्याय-2

कराधायक प्राधिकारी

3. (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के कराधायक लिए, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी व्यक्ति को आबकारी एवं प्राधिकारी। कराधान आयुक्त के रूप में और ऐसे अन्य व्यक्तियों को ऐसे पदनामों के साथ जैसा वह उचित समझे, नियुक्त कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इतने निर्धारण प्राधिकारी नियुक्त कर सकेगी जितने वह उचित समझे।

(3) उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त आयुक्त और अन्य व्यक्ति ऐसे कृत्यों और कर्तव्यों का पालन करेंगे जो इस अधिनियम द्वारा या के अधीन अपेक्षित हों या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्रदत्त किए जाएं।

(4) आयुक्त और राज्य मुख्यालय में तैनात अन्य अधिकारियों की अधिकारिता का विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य में होगा और अन्य अधिकारियों या कर्मचारियों की अधिकारिता का विस्तार, जब तक कि राज्य सरकार अन्यथा निदेशित न करे, अधिसूचना द्वारा जिलों या जिलों के उन क्षेत्रों, जिनमें कि वे तत्समय तैनात हैं, विस्तारित किया जाएगा।

अध्याय-3

कर का भार, उद्ग्रहण, संग्रहण और छूट

4. (1) वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर का ऐसी दरों पर, जो प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष दो हजार पांच सौ रुपये से उद्ग्रहण। अधिक नहीं होगी, कर उद्गृहीत और संगृहीत किया जाएगा।

(2) राज्य में किसी वृत्ति, व्यापार, आजीविका या नियोजन में विनियुक्त और अनुसूची-1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट किन्हीं प्रवर्गों के अन्तर्गत आने वाला प्रत्येक व्यक्ति उप-धारा (1) के अधीन उद्गृहीत कर को, उसके स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर, संदत्त करने के लिए दायी होगा ।

नियोजकों
का
कर्मचारियों
की ओर से
कर की
कटौती करने
और उसका
संदाय करने
का दायित्व।

5. इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा संदेय कर की, उसके नियोजक द्वारा ऐसे व्यक्ति को संदेय वेतन या मजदूरी में से, उसे ऐसे वेतन या मजदूरी को संदत्त करने से पूर्व, कटौती की जाएगी और, चाहे ऐसी कटौती की हो या न की हो, का विचार किए बिना वह ऐसे व्यक्ति की ओर से कर संदत्त करने का दायी होगा:

परन्तु यह कि नियोजक सरकार, दायित्व का विहित रीति में निर्वहन करेगी :

परन्तु यह और कि जहां वेतन या मजदूरी उपार्जित करने वाला कोई व्यक्ति एक से अधिक नियोजक के नियोजन में समसामयिक रूप से विनियुक्त है और यदि ऐसा व्यक्ति, विहित प्ररूप में इस प्रभाव का, अपने नियोजक या नियोजकों को प्रमाण पत्र देता है, कि वह इस अधिनियम के अधीन स्वयं को नामांकित (इन्रोल) करवा लेगा, तो ऐसा नियोजक या ऐसे नियोजक, उसे देय वेतन या मजदूरी में से कर की कटौती नहीं करेगा/करेंगे और, यथास्थिति, ऐसा नियोजक या ऐसे नियोजक उसकी ओर से कर संदत्त करने का दायी नहीं होगा/होंगे ।

कर से छूट।

6. (1) अनुसूची-2 के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा कोई भी कर संदेय नहीं होगा ।

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा अनुसूची-1 या अनुसूची-2 में परिवर्धन या लोप या अन्यथा संशोधन कर सकेगी और तदुपरि अनुसूचियां तदनुसार संशोधित की गई समझी जाएंगी ।

अध्याय-4

रजिस्ट्रीकरण और नामांकन

7. (1) इस अधिनियम के अधीन कर संदत्त करने के लिए दायी प्रत्येक नियोजक, जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी संघ राज्य क्षेत्र की सरकार का अधिकारी न हो, निर्धारण प्राधिकारी से विहित रीति में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र अभिप्राप्त करेगा।

(2) वेतन या मजदूरी उपार्जित करने वाले व्यक्ति से अन्यथा, इस अधिनियम के अधीन कर संदत्त करने का दायी प्रत्येक व्यक्ति, जिसकी बाबत उसके नियोजक द्वारा कर संदेय है, निर्धारण प्राधिकारी से विहित रीति में नामांकन (इन्रोलमेंट) प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करेगा।

(3) रजिस्ट्रीकरण या नामांकन प्रमाण पत्र अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक नियोजक या व्यक्ति को इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से तीस दिन के भीतर, या यदि वह उस तारीख को किसी वृत्ति, व्यापार, आजीविका या नियोजन में विनियुक्त नहीं था, उसके कर संदत्त करने के लिए दायी होने के तीस दिन के भीतर या उप-धारा (2) में निर्दिष्ट व्यक्ति की बाबत, उसके नामांकन प्रमाण पत्र में वर्णित से उच्चतर या निम्न दर पर कर संदत्त करने के लिए दायी होने के तीस दिन के भीतर, निर्धारण प्राधिकारी को, विहित प्ररूप में, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण या नामांकन प्रमाणपत्र या पुनरीक्षित प्रमाणपत्र या नामांकन के लिए आवेदन करेगा और निर्धारण प्राधिकारी ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी आवश्यक हो, आवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उसे ऐसा प्रमाण पत्र प्रदान करेगा:

परन्तु यह कि जहां कर की दर के पुनरीक्षण के कारण वह व्यक्ति जो नामांकन प्रमाण पत्र में वर्णित से उच्चतर या निम्न दर पर कर का संदाय करने के लिए दायी है तो ऐसे

प्रमाणपत्र में वर्णित कर की दर, यथापूर्वोक्त ऐसे कर की दर के पुनरीक्षण की तारीख को तदनुसार पुनरीक्षित की गई समझी जाएगी; और आवेदन लम्बित रहने तक, पुनरीक्षित प्रमाणपत्र या नामांकन के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति, इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी पुनरीक्षित दर पर कर संदत्त करने का दायी होगा ।

(4) निर्धारण प्राधिकारी प्रत्येक नामांकन प्रमाणपत्र में धारक द्वारा, अधिसूचित दरों के अनुसार, संदेय कर की रकम और तारीख जिस तक इसे संदत्त किया जाना है वर्णित करेगा; और ऐसा प्रमाण पत्र, उप-धारा (3) के परन्तुक के उपबन्धों के अध्यधीन वसूली के प्रयोजनों के लिए मांग की सूचना (नोटिस ऑफ डिमान्ड) के रूप में तामील करेगा ।

(5) जहां रजिस्ट्रीकरण या नामांकन के लिए दायी कोई नियोजक या कोई व्यक्ति जानबूझकर अपेक्षित समय के भीतर, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण या नामांकन प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने में असफल रहा है तो निर्धारण प्राधिकारी उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्,—

- (i) नियोजक की दशा में, विलम्ब के प्रत्येक दिन के लिए दस रूपए से अनधिक किन्तु दो हजार से अनधिक शास्ति; और
- (ii) अन्य की दशा में दस रूपए प्रति दिन से अनधिक किन्तु किसी एक मामले में एक हजार रूपए से अनधिक शास्ति,

अधिरोपित कर सकेगा ।

(6) जहां रजिस्ट्रेशन या नामांकन के लिए दायी किसी नियोजक या व्यक्ति ने इस धारा के अधीन प्रस्तुत किसी आवेदन में

जानबूझ कर मिथ्या सूचना दी है, तो निर्धारण प्राधिकारी उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् उस पर एक हजार रूपए से अनधिक शास्ति अधिरोपित कर सकेगा ।

अध्याय-5

कर की विवरणी, निर्धारण, संदाय, वसूली और संग्रहण

8. इस अधिनियम के अधीन संदेय कर विहित रीति में कर का ऐसे अन्तरालों पर, जैसे विहित किए जाएं, संदत्त किया जाएगा। संदाय ।

9. (1) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक विवरणियां नियोजक, निर्धारण प्राधिकारी को, ऐसे प्ररूप में, ऐसी अवधियों के दाखिल लिए और ऐसी तारीखों तक, जैसी विहित की जाए, विवरणी प्रस्तुत करना । करेगा ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन प्रस्तुत की गई ऐसी प्रत्येक विवरणी के साथ, ऐसी विवरणी के अनुसार देय कर की पूर्ण रकम के संदाय के प्रमाण के रूप में खजाना चालान संलग्न किया जाएगा, और कर के संदाय के ऐसे प्रमाण के बिना कोई विवरणी, सम्यक् रूप से प्रस्तुत नहीं की गई समझी जाएगी ।

(3) जहां कोई नियोजक युक्तियुक्त कारण के बिना अपेक्षित समय के भीतर ऐसी विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहा है तो विहित प्राधिकारी उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् विलम्ब के प्रत्येक दिन के लिए दस रूपए से अनधिक शास्ति अधिरोपित कर सकेगा परन्तु जो कुल मिला कर दायित्व के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकेगी ।

10. (1) यदि निर्धारण प्राधिकारी का समाधान हो जाता है निर्धारण । कि किसी नियोजक द्वारा प्रस्तुत विवरणी सही और पूर्ण है तो इसे

स्वीकृत किया गया मान लिया जाएगा :

परन्तु यदाकदा आधार पर आयुक्त इस धारा के प्रयोजन के लिए ऐसी सीमा तक, जैसी अधिसूचित की जाए, विवरणियों की जांच की अपेक्षा कर सकेगा ।

(2) (क) यदि निर्धारण प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि सम्यक् रूप से दाखिल की गई विवरणी सही या पूर्ण नहीं है तो वह नियोजक पर नोटिस की तामील करेगा जिसमें उससे नोटिस में दी गई तारीख को, व्यक्तिगत रूप में या प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा हाजिर होने और विवरणी के समर्थन में लेखे और कागज-पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा ।

(ख) निर्धारण प्राधिकारी, लेखे और कागज-पत्र का परीक्षण करने के पश्चात् नियोजक द्वारा संदेय कर की रकम का निर्धारण करेगा ।

(ग) यदि नियोजक नोटिस के निबन्धनों का अनुपालन करने में असफल रहता है या यदि निर्धारण प्राधिकारी की राय में लेखे और कागज-पत्र सही या पूर्ण या विश्वसनीय नहीं है, तो ऐसा प्राधिकारी, ऐसी जांच के पश्चात् जैसी वह उचित समझे, या अन्यथा, अपनी पूर्ण विवेक बुद्धि से कर का निर्धारण करेगा ।

(3) किसी भी नियोजक से देय कर की रकम, प्रत्येक वर्ष के लिए या उस के किसी भाग के लिए, जिसके दौरान वह कर संदत्त करने के लिए दायी था, पृथकतः निर्धारित की जाएगी ।

(4) यदि कोई नियोजक स्वयं को रजिस्ट्रीकृत करवाने में असफल रहा है या रजिस्ट्रीकृत होते हुए भी कोई विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहा है या निर्धारण से बच निकला है तो निर्धारण प्राधिकारी, नियोजक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के

पश्चात् और ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह उचित समझे, या अन्यथा अपनी पूर्ण विवेक बुद्धि से देय कर की रकम का निर्धारण करते हुए आदेश पारित करेगा ।

(5) कर की ऐसी निर्धारित रकम, निर्धारण प्राधिकारी से नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर, संदत्त की जाएगी।

(6) इस धारा के अधीन कोई भी आदेश, उस वर्ष की समाप्ति, जिसके बारे में या जिसके किसी भाग के लिए निर्धारण किया गया है से, दो वर्ष के अवसान के पश्चात्, पारित नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह कि यदि कार्यवाहियां, यथास्थिति, अपीलीय प्राधिकारी या सक्षम न्यायालय द्वारा रोक दी जाती है तो रोक की अवधि, उक्त दो वर्ष की अवधि की संगणना करने में अपवर्जित की जाएगी :

परन्तु यह और भी कि, जहां किसी अपीलीय प्राधिकारी या सक्षम न्यायालय के किसी आदेश के परिणामस्वरूप या इसे प्रभावी करने के लिए कोई निर्धारण आदेश पारित किया जाता है, तो इसे निर्धारण प्राधिकारी को ऐसे आदेश की संसूचना के एक वर्ष के भीतर संपूरित किया जाएगा ।

11. (1) यदि कोई निर्धारित, जो राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार का कोई अधिकारी नहीं है, वेतन या मजदूरी के संदाय के समय कर की कटौती नहीं करता है या कटौती करने के पश्चात् इस अधिनियम के द्वारा या के अधीन यथाअपेक्षित कर का संदाय करने में असफल रहता है तो वह--

(क) कर की बाबत व्यतिक्रमी निर्धारित समझा जाएगा; और

(ख) उस अवधि के लिए जिसके लिए कर असंदत्त रहता है,

प्रत्येक माह या उसके भाग के लिए कर की देय रकम पर एक प्रतिशत प्रति माह की दर से ऐसे ब्याज का संदाय करने के लिए दायी होगा ।

(2) यदि कोई नामांकित(इनरोल्ड) व्यक्ति इस अधिनियम द्वारा या के अधीन यथा अपेक्षित कर का संदाय करने में असफल रहता है तो वह उप-धारा (1) के अधीन उपबंधित दर पर और रीति में ब्याज संदत्त करने के लिए दायी होगा ।

कर के असंदाय के लिए शास्ति। 12. (1) यदि कोई निर्धारित, मांग की सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर, युक्तियुक्त कारण के बिना कर की किसी रकम का संदाय करने में असफल रहता है, तो निर्धारण प्राधिकारी, उसे अपना अभ्यावेदन देने के लिए युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, उस पर शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो देय कर की रकम के पंद्रह प्रतिशत से कम नहीं होगी परन्तु पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

कर की वसूली । 13. इस अधिनियम के अधीन मांग की सूचना के पश्चात् कर, शास्ति, ब्याज या असंदत्त रही किसी अन्य रकम का बकाया, भू-राजस्व के रूप में वसूलीय होगा ।

इस अधिनियम के अधीन दायित्व का प्रथम प्रभार होना । 14. तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा कर की कोई राशि और संदेय कोई अन्य रकम, ऐसे व्यक्ति की सम्पत्ति पर प्रथम प्रभार होगी ।

वसूली का विशेष ढंग। 15. तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या संविदा में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, निर्धारण प्राधिकारी, किसी भी समय लिखित नोटिस द्वारा, जिसकी एक प्रति निर्धारित को उसके अन्तिम ज्ञात पते पर भेजी जाएगी--

(क) किसी भी व्यक्ति से, जिससे निर्धारित को, धन की कोई रकम देय है या देय हो जाए, जिस पर इस अधिनियम के अधीन मांग के नोटिस की तामील की गई है, या

(ख) किसी भी व्यक्ति से, जो ऐसे निर्धारित के लिए या के मद्धे धन धारण करता है या तत्पश्चात् धारण कर सकेगा,

धन देय होने या धारण करने पर या तो तत्काल या नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर, परन्तु उपर्युक्त रूप में यथापूर्वोक्त रूप में धन देय होने या इससे धारित करने से पूर्व नहीं उतना धन जो इस अधिनियम के अधीन कर शास्ति और ब्याज की बकाया रकम को संदत्त करने में पर्याप्त है, या संपूर्ण धन जब यह उस रकम के बराबर या उससे कम है, निर्धारण प्राधिकारी को संदत्त करने की अपेक्षा करेगा ।

16. निर्धारण प्राधिकारी, किसी व्यक्ति को, उस द्वारा देय प्रतिदाय । रकम से अधिक संदत्त की गई कर की रकम, शास्ति, ब्याज और फीस का, यदि कोई हो, प्रतिदाय करेगा और प्रतिदाय, विहित रीति में, या तो नकद संदाय द्वारा या व्यक्ति के विकल्प पर, किसी अन्य अवधि के बारे में देय कर की रकम, शास्ति, ब्याज और फीस में से, ऐसे आधिक्य की कटौती द्वारा, किया जा सकेगा :

परन्तु यह कि निर्धारण प्राधिकारी, प्रथमतः ऐसे आधिक्य को, किसी देय रकम, जिस की बाबत धारा 10 की उप-धारा (5) के अधीन नोटिस की तामील की गई है, की वसूली के लिए उपयोजित करेगा और तत्पश्चात् बकाया का, यदि कोई हो, प्रतिदाय करेगा ।

17. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, राज्य सरकार या स्थानीय वसूली एजेंटों की नियुक्ति।

प्राधिकरण के किसी अधिकारी को अपना वसूली एजेंट नियुक्त कर सकेगी जो ऐसे निर्धारितियों से, जैसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, इस अधिनियम के अधीन कर का संग्रहण करने के लिए, दायी होगा और तदुपरि ऐसा वसूली एजेंट, उसे समनुदेशित प्रयोजन के लिए कृत्यों का पालन करेगा ।

अध्याय-6

अपील और पुनरीक्षण

अपील । 18. (1) निर्धारण प्राधिकारी द्वारा पारित प्रत्येक मूल आदेश से अपील उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त को होगी ।

(2) उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा अपील में पारित आदेश, आगे आयुक्त को अपीलीय होगा ।

(3) कोई भी अपील उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, की संसूचना की तारीख से साठ दिन की अवधि या ऐसी दीर्घतर अवधि, जिसे अपील प्राधिकारी कारणों को लिखित में अभिलिखित करके अनुज्ञात करे, के अवसान के पश्चात् ग्रहण नहीं की जाएगी ।

(4) किसी भी अपील प्राधिकारी द्वारा उप-धारा (1) या (2) के अधीन कोई भी अपील तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी, जब तक ऐसी अपील के साथ, यथास्थिति, कर (संदेय ब्याज सहित) या शास्ति, यदि कोई अधिरोपित की गई हो, या दोनों के संदाय का समाधानप्रद सबूत संलग्न न हो :

परन्तु यदि ऐसे प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि निर्धारित, निर्धारित कर (संदेय ब्याज सहित) या शास्ति, यदि कोई अधिरोपित की गई हो या दोनों, संदत्त करने में असमर्थ

है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करते हुए, बिना कर के (संदेय ब्याज सहित) के या शास्ति के अथवा दोनों पूर्णतया संदत्त किए जा चुके हों या ऐसे कर (संदेय ब्याज सहित) या शास्ति या दोनों के आंशिक संदाय के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा ।

(5) प्रक्रिया के ऐसे नियमों के अध्याधीन जो विहित किए जाएं, अपील प्राधिकारी, अपील पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह न्याय संगत और उचित समझे ।

19. (1) आयुक्त स्वप्रेरणा से, कार्यवाहियों, जो, यथास्थिति, आयुक्त द्वारा किसी निर्धारण प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी के समक्ष लम्बित है पुनरीक्षण । या निपटाई गई है, के अभिलेख को ऐसी कार्यवाहियों या उनमें किए गए आदेश की वैधता और औचित्य के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए, मंगवा सकेगा और परीक्षण कर सकेगा और कार्यवाहियों या आदेशों को राजस्व के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले प्रतीत होने पर उनके सम्बन्ध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह ठीक समझे ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन कोई भी आदेश, जो किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो ।

20. (1) धारा 18 की उप-धारा (2) या धारा 19 के अधीन उच्च पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति या प्राधिकारी, ऐसे आदेश को तामील की तारीख से नब्बे दिन के भीतर, ऐसे आदेश के पुनरीक्षण के लिए, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय को आवेदन कर सकेगा, यदि उसमें विधि के गलत विनिश्चय से उद्भूत होने वाला विधि का कोई प्रश्न या विधि के किसी प्रश्न का विनिश्चय करने में असफलता अन्तर्वलित हो ।
उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण ।

(2) उच्च न्यायालय पुनरीक्षण में पक्षकारों को सुनने के पश्चात् इसे कथित या इस द्वारा बनाए गए विधि के प्रश्न का विनिश्चय करेगा और तदुपरि उस पर ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा विधि के प्रश्न का विनिश्चय करने के लिए आवश्यक हो ।

अध्याय-7

लेखे

नियोजक
या किसी
व्यक्ति
द्वारा लेखों
का
अनुरक्षण।

21. (1) यदि आयुक्त का समाधान हो जाता है कि नियोजकों के किसी विशिष्ट वर्ग द्वारा, उनके कारबार के सामान्य अनुक्रम में, अनुरक्षित लेखा बहियां और अन्य दस्तावेज, ऐसे नियोजक द्वारा दी गई विवरणियों के सत्यापन के लिए पर्याप्त नहीं हैं, तो वह उसे, लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों को ऐसी रीति में, जो विहित की जा सकेगी, अनुरक्षित करने के लिए लिखित में निदेश कर सकेगा और तदुपरि ऐसा नियोजक तदनुसार ऐसी लेखा बहियां और अन्य दस्तावेज अनुरक्षित रखेगा ।

(2) जहाँ नियोजक जानबुझ कर, उप-धारा (1) के अधीन यथा निदेशित, लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों को अनुरक्षित रखने में असफल रहता है, तो निर्धारण प्राधिकारी उसको सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् एक हजार रुपये अधिकतम के अध्याधोन, ऐसे व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन के लिए पचास रुपये से अनधिक की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा ।

अध्याय-8

अपराध, शास्तियां और अपराधों का शमन

अपराध और
शास्तियां ।

22. कोई भी व्यक्ति या नियोजक, जो बिना पर्याप्त हेतुक के इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के किसी उपबन्ध का पालन करने में असफल रहता है, तो निर्धारण प्राधिकारी निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति या नियोजक एक हजार रुपये से अनधिक

की राशि शास्ति के रूप में संदत्त करेगा और जहां जारी रहने वाला अपराध हो, पच्चीस रूपए प्रतिदिन से अनधिक शास्ति अपराध के जारी रहने की अवधि के दौरान, संदत्त करेगा ।

23. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कम्पनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था तो ऐसा व्यक्ति तथा कम्पनी दोनों संयुक्ततः या पृथक्ततः ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और अधिनियम में यथा उपबन्धित शास्ति के लिए दायी होंगे:

परन्तु इस उप-धारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को किसी शास्ति के लिए दायी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और अधिनियम में यथा उपबन्धित शास्ति के लिए दायी होगा।

स्पष्टीकरण.— इस धारा के प्रयोजन के लिए “कम्पनी” से निगमित निकाय अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है; और फर्म के सम्बन्ध में “निदेशक” से फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

अपराधों का
शमन ।

24. (1) ऐसी शर्तों के अधीन, जो विहित की जा सकेंगी, निर्धारण प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के प्रारम्भ से पूर्व या पश्चात्, किसी अपराध का, ऐसी रकम के संदाय पर, जो अधिनियम के अधीन उपबन्धित अधिकतम शास्ति के पच्चीस प्रतिशत से कम नहीं होगी परन्तु जो पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, शमन कर सकेगा ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अपराध का शमन होने पर, उसी अपराध की बाबत, व्यक्ति के विरुद्ध कोई और कार्यवाहियाँ नहीं की जा सकेंगी ।

अध्याय-9

प्रकीर्ण

हाजिर
कराने और
साक्ष्य लेने
की
शक्ति।

25. इस अधिनियम के अधीन समस्त प्राधिकारियों को, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, किसी वाद का विचारण करते समय किसी व्यक्ति को हाजिर कराने और शपथ या प्रतिज्ञान पर उसकी परीक्षा कराने या किसी दस्तावेज को पेश कराने के लिए बाध्य करने की बाबत, वही शाक्तियाँ प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित है ।

1908 को 5

कतिपय
कार्यवाहियों
का वर्जन।

26. इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी निर्धारण या पारित किसी आदेश को अपास्त या उपांतरित करने के लिए कोई भी वाद किसी सिविल न्यायालय में नहीं होगा ।

परित्राण
(इन्डैमनिटी)

27. इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने को आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियाँ इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी के विरुद्ध या किसी नियोजक के विरुद्ध नहीं होंगी ।

28. ऐसे निर्बन्धों और शर्तों के अधीन, जो विहित की शक्तियों का जाएं, आयुक्त लिखित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के अधीन अपनी प्रत्यायोजन। किसी भी शक्ति को किसी अधिकारी को, जो राज्य मुख्यालय में तैनात अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त की पंक्ति से नीचे का न हो, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

29. (1) स्थानीय प्राधिकरण के संविधान या स्थापना को स्थानीय शासित (विनियमित) करने वाली किसी अधिनियमिति में, किसी बात प्राधिकरणों के होते हुए भी, कोई भी स्थानीय प्राधिकरण, इस अधिनियम के द्वारा वृत्ति-कर प्रारम्भ को या पश्चात् वृत्तियों, व्यावसायों, व्यापारों, आजीविकाओं या का नियोजनों पर कर का उद्ग्रहण नहीं करेगा। उद्ग्रहण नहीं।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी किसी विधि के अधीन वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर लगाए गए कर पर कोई उप कर उद्ग्रहीत नहीं किया जाएगा और ऐसी विधि में, ऐसे उद्ग्रहण और संग्रहण को प्राधिकृत करने वाले उपबन्ध इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को, और से निरसित हो जाएंगे।

30. इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल संक्रमणकालीन होते हुए भी, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 उपबन्ध। के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करने वाला कोई प्राधिकारी और कर की कटौती और सरकारी खजाने में इसके संदाय, विवरणी और चालान दाखिल करने सम्बन्धी किसी नियम, जहाँ तक ये मूल्य परिवर्धित कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के प्रयोजनों के लिए लागू हों, अधिनियम के अधीन कर की कटौती और संदाय के प्रयोजनों के लिए यथावश्यक परिवर्तनों सहित, जब तक इस अधिनियम के अधीन नियम नहीं बना दिए जाते या इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से छः मास के अवसान तक, जो भी पहले हो, लागू होंगे।

31. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, कर के नियम बनाने उद्ग्रहण और संग्रहण को सुनिश्चित करने और साधारणतया इस की शक्ति।

अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, इस अधिनियम से संगत, नियम बना सकेगी ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष, यदि वह सत्र में हो और यदि यह सत्र में नहीं है, तो तुरन्त बाद के सत्र में, कुल चौदह दिन की अवधि के लिए जो कि एक सत्र में या दो आनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के अवसान के पूर्व जिसमें यह इस तरह रखा गया था या शीघ्र-बाद के सत्र में, विधान सभा नियम में कोई उपान्तरण करने या नियम को निष्प्रभाव करने का विनिश्चय करती है तो नियम उस तारीख से जिस को ऐसा उपान्तरण या निष्प्रभाव अधिसूचित किया जाता है, तो नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में, यथास्थिति, प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जाएगा, किन्तु नियम के ऐसे उपान्तरित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अनुसूची-1
(धारा 4 और 6 देखें)

क्रम संख्या	निर्धारितियों के वर्ग	कर की दर
1	2	3

1. मासिक वेतन और मजदूरी प्राप्त, वेतन
और मजदूरी उपार्जित करने वाले:

(i)	प्रतिमास 4000/- रुपये तक,	-शून्य-
(ii)	4001/- रुपये से 10,000/- रुपये तक का वेतन	100/- रुपये प्रतिमास
(iii)	10001/- रुपये से 15,000/- रुपये तक का वेतन	150/- रुपये प्रतिमास
(iv)	15001/- रुपये से अधिक वेतन	200/- रुपये प्रतिमास

2 (क) सालिसिटरज, नोटरीज पब्लिक, तकनीकी
और वृत्तिक परामर्शियों, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स,
वास्तुविदों सहित विधिक व्यवसायी जिनकी
व्यवसाय में अवस्थिति/प्रेक्टिस इस प्रकार
है,--

(i)	पांच वर्षों तक,	-शून्य-
(ii)	पांच वर्ष से दस वर्ष के मध्य	50/- रुपये प्रतिमास
(iii)	दस वर्ष से पन्द्रह वर्ष के मध्य	150/- रुपये प्रतिमास
(iv)	पन्द्रह वर्ष से अधिक	200/- रुपये प्रतिमास

(ख)	विलेख/दस्तावेज लेखक	100/- रुपये प्रतिमास
-----	---------------------	----------------------

1	2	3
3	(क) बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) के अधीन रजिस्ट्रीकृत या अनुज्ञप्त मुख्य अभिकर्ता, प्रधान अभिकर्ता, बीमा अभिकर्ता और सर्वेयर या हानि निर्धारक (लॉस असेसर)	200/- रुपये प्रतिमास
	(ख) राष्ट्रीय लघु बचत स्कीमों के अधीन डाक अभिकर्ता (जिनका उपार्जन प्रतिवर्ष 48,000/- रुपये से अधिक है)	100/- रुपये प्रतिमास
4.	प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 के अधीन मान्यता प्राप्त शेयर बाजारों के सदस्य, नीलामकर्ता, कमीशन अभिकर्ता	200/- रुपये प्रतिमास
5.	(क) संपदा अभिकर्ता या दलाल	200/- रुपये प्रतिमास
	(ख) लोक निर्माण विभाग के ठेकेदार(सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शनों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत और संविदा कार्यों को सक्रिय रूप में निष्पादित कर रहे),--	
	(i) "क" श्रेणी ठेकेदार	200/- रुपये प्रतिमास
	(ii) "ख" श्रेणी ठेकेदार	200/- रुपये प्रतिमास
	(iii) "ग" श्रेणी ठेकेदार	150/- रुपये प्रतिमास
	(iv) "घ" श्रेणी ठेकेदार	50/- रुपये प्रतिमास
	(ग) वन ठेकेदार	150/- रुपये प्रतिमास
	(घ) कोई अन्य ठेकेदार	100/- रुपये प्रतिमास
6.	कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कम्पनियों के (सरकार द्वारा नाम निर्देशित से भिन्न) निदेशक	200/- रुपये प्रतिमास

1

2

3

7. हिमाचल प्रदेश साधारण विक्रय कर अधिनियम, 1968 (1968 का 24), हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का 12) और केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) के अधीन रजिस्ट्रीकृत और रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी व्यौहारी, खादी और ग्रामोद्योग इकाईयां, जिनका वार्षिक आवर्त हो: -

(i) चार लाख रुपये तक

-शून्य-

(ii) चार लाख रुपये से दस लाख के मध्य

100/- रुपये प्रतिमास

(iii) दस लाख रुपये से पच्चीस लाख के मध्य

150/- रुपये प्रतिमास

(iv) पच्चीस लाख रुपये से अधिक

200/- रुपये प्रतिमास

8. कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) के अधीन यथापरिभाषित कारखाने का अधिष्ठाता जो मद संख्या 7 के अन्तर्गत नहीं आता है

200/- रुपये प्रतिमास

9. पेट्रोल/डीजल/विमानन टर्बाइन ईन्धन फिलिंग स्टेशनन और सर्विस स्टेशनज, गैरेज और आटोमोवाईल वर्कशापज के स्वामी या पट्टेदार ।

200/- रुपये प्रतिमास

10. चावलमिल, तेल मिल, स्पीनिंग मिल, पेपर मिल, दाल मिल, पावरलूम, लघु इस्पात संयंत्र, रिरोलिंग मिल, खाण्डसारी चीनी कारखाना, चीनी कारखाना, फाउंडरी, टैनरी, स्टोन क्रशर, वाटलिंग यूनिट, डिस्टलरी, टाईल कारखाना, बिस्कुट कारखाना, रसायन और औषधिय प्रयोगशाला, मुद्रणालय (बिजली के साथ), फल डिब्बा बन्दी इकाई, के मालिक और पट्टेदार

200/- रुपये प्रतिमास

11. हिमाचल प्रदेश दुकान एवं वाणिज्यिक स्थापन

1	2	3
	अधिनियम, 1969 के अधीन यथा परिभाषित स्थापन के नियोजक (जो मद-7 के अन्तर्गत न आने वाले व्यौहारी हैं) जिनके पास:-	
	(i) कोई कर्मचारी नहीं है	-शून्य-
	(ii) पांच से अधिक कर्मचारी नहीं हैं	50/- रुपये प्रतिमास
	(iii) पांच से अधिक कर्मचारी परन्तु दस से अधिक नहीं	100/- रुपये प्रतिमास
	(iv) दस से अधिक कर्मचारी परन्तु बीस से अधिक नहीं	150/- रुपये प्रतिमास
	(v) बीस से अधिक कर्मचारी	200/- रुपये प्रतिमास
12.	राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाए जाने वाले से अन्यथा नर्सिंग होम या अस्पताल के स्वामी या पट्टेधारी	200/- रुपये प्रतिमास
13.	(क) दस से अन्यून कमरों वाले आवासीय होटल या हाउसिंग लॉजिंग	200/- रुपये प्रतिमास
	(ख) गैस्ट हाउस और सराय	100/- रुपये प्रतिमास
	(ग) (i) नाट्यशाला का स्वामी	200/- रुपये प्रतिमास
	(ii) टूरिंग टॉकी का स्वामी	200/- रुपये प्रतिमास
	(iii) विडीयो पार्लर का स्वामी :-	
	(क) शहरी क्षेत्र में	100/- रुपये प्रतिमास
6.	(ख) ग्रामीण क्षेत्र में	50/- रुपये प्रतिमास
	(iv) केवल टीवी आपरेटर	
	(क) नगरपालिका क्षेत्र में	100/- रुपये प्रतिमास
	(ख) ग्रामीण क्षेत्र में	50/- रुपये प्रतिमास
14.	बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में यथापरिभाषित बैंकिंग कम्पनी	200/- रुपये प्रतिमास

1	2	3
15.	कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकृत समस्त कम्पनियां जो वृत्ति व्यापार या अजीविका में लगी है	200/- रुपये प्रतिमास
16.	दन्त चिकित्सकों, विकिरण चिकित्सा विज्ञानिकों, विकृति विज्ञान चिकित्सकों और सह-चिकित्सीय प्रकृति की वृत्तियों या आजीविका में लगे व्यक्तियों सहित समस्त चिकित्सा व्यवसायी	200/- रुपये प्रतिमास
17.	फिल्म वितरक, समस्त प्रकार के यात्रा अभिकर्ता और विज्ञापन फर्म/अधिकरण	200/- रुपये प्रतिमास
18.	पत्रकार :-	
	(क) राज्य स्तरीय	200/- रुपये प्रतिमास
	(ख) जिला स्तरीय	100/- रुपये प्रतिमास
	(ग) उप-मण्डल स्तरीय	50/- रुपये प्रतिमास
19.	(क) कार्य सर्कम (जॉब वर्क) के लिए फोटो काफ़ी मशीन का स्वामित्व रखने वाले व्यक्ति:-	
	(i) शहरी क्षेत्रों में	100/- रुपये प्रतिमास
	(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में	50/- रुपये प्रतिमास
	(ख) कोचिंग (खेलों से भिन्न) टंकण, मुद्रण, लैमिनेशन इत्यादि की सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले व्यक्ति ।	200/- रुपये प्रतिमास
20.	शैक्षणिक संस्थाएं, शिक्षकीय महाविद्यालय, संस्थान (राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वधीन से अन्यथा)	200/- रुपये प्रतिमास

1	2	3
21.	भू-विकासक और भवन/फ्लैट विकासक सहित सम्पत्ति विकासक	200/- रुपये प्रतिमास
22.	निम्नलिखित का स्वामित्व रखने/निम्नलिखित चलाने वाले:-	
	(क) कम्प्यूटर संस्थान सैलिंग टाईम	100/- रुपये प्रतिमास
	(ख) कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थान या ई-कैफे	200/- रुपये प्रतिमास
	(ग) डाइविंग संस्थान/तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान	100/- रुपये प्रतिमास
	(घ) विडियो कैसेट लाइब्रेरी	200/- रुपये प्रतिमास
	(ङ) नगरपालिका क्षेत्रों में इन्डोर गेम्ज या स्वास्थ्य सुविधाएं	200/- रुपये प्रतिमास
23.	विवाह हालों का स्वामित्व रखने वाले व्यक्ति और इन्हें किराए पर देने वाले या विवाह समारोह/समारोहों के लिए संदाय पर साउंड, लाईटिंग, फर्नीचर, टेंट हाउसिज, शामियाना इत्यादि उपलब्ध करवाने वाले अभिकरण	200/- रुपये प्रतिमास
24.	(क) अग्रेषण और निकासी अभिकर्ता सहित परिवहन कम्पनियां और परिवहन संविदाकार	200/- रुपये प्रतिमास
	(ख) बैंकर जो हुण्डियों के विरुद्ध व्यापार को, या ब्याज पर लघु अवधि अग्रिम के रूप में अन्य प्रतिभूतियों का वित्तपोषण कर रहे हैं	200/- रुपये प्रतिमास
25.	(क) शेयर बाजार द्वारा मान्यता प्राप्त प्राधिकृत सहायक	200/- रुपये प्रतिमास
	(ख) कोरियर सेवा का संचालन करने वाले व्यक्ति	200/- रुपये प्रतिमास

1

2

3

26. निम्न का परिचालन करने वाले व्यक्ति :-

- | | | |
|-----|--|----------------------|
| (क) | शहरी क्षेत्र में आई.एस.डी, एस.टी.डी. बूथ | 100/- रुपये प्रतिमास |
| (ख) | कोल्ड स्टोरेज | 200/- रुपये प्रतिमास |
| (ग) | शहरी क्षेत्रों में बीस से अधिक यानों की
मोटर यान पार्किंग । | 200/- रुपये प्रतिमास |

अनुसूची-2
(धारा 6 देखें)

क्रम संख्या	निर्धारितियों का वर्ग
1.	दैनिक मजदूरी कमाने वाले ।
2.	राज्य सरकार द्वारा संविदा के आधार पर भाड़े पर लिए गए कर्मचारी।
3.	सहकारी सोसाइटियां ।
4.	चार लाख रुपये तक की आवर्त वाले छोटे और खुदरा व्यापारी ।
5.	फलों/घानियों सहित कृषक, गांवों में सभाल सेवा प्रदान करने वाले जैसे कि बढई, लोहार और ग्रामीण शिल्पी, बारबर, नाई, धोबी, घराटी, तेली, कसाई इत्यादि (शहरी क्षेत्रों में ब्यूटी पार्लर और सैलून के सिवाए) ।
6.	स्वतन्त्रता सेनानी ।
7.	पेंशन भोगी ।
8.	केन्द्रीय पैरामिलिट्री पर्सनलज सहित थल सेना, जल सेना और वायु सेना के पर्सनलज ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य सरकार से, निर्धनों के फायदे के लिए विस्तारित सामाजिक सुरक्षा मदद का वित्तपोषण करना अपेक्षित है, इसलिए आवश्यक विधान अधिनियमित करके राज्य में वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर का उद्ग्रहण करने का विनिश्चय किया गया है ।

यह विधेयक, उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

रंगीला राम राव,
प्रभारी मन्त्री ।

शिमला:

.....2005.

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 4, अनुसूची-1 के स्तम्भ (2) के अधीन विनिर्दिष्ट निर्धारितियों के वर्गों की वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर, इसके स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दरों पर कर के उद्ग्रहण का प्रस्ताव करता है। विधेयक के उपबन्धों के अधिनियमित होने पर, राजकोष को प्रतिवर्ष लगभग पैतालीस करोड़ रुपये की आय होना अनुमानित है। विधेयक के उपबन्ध, अधिनियमित किए जाने के पश्चात्, विद्यमान सरकारी तन्त्र द्वारा प्रवर्तित किए जाएंगे इसलिए कोई अतिरिक्त व्यय अन्तर्वलित नहीं होगा।

प्रत्यायोजित विधान सम्बंधी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 30 राज्य सरकार को इस विधेयक के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करता है। यह प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य प्रकृति का है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारशें।

(नस्ति संख्या ई.एक्स.एन.-एफ(6)2/2005)

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर विधेयक, 2005 की विषयवस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को राज्य विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

हिमाचल प्रदेश वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर विधेयक, 2005

कि

हिमाचल प्रदेश राज्य में वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर के उद्ग्रहण और संग्रहण का उपबन्ध करने के लिए विधेयक ।

रंगीला राम राव,
प्रभारी मन्त्री ।

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर,
सचिव (विधि) ।

शिमला:

तीसरी अप्रैल, 2005

Bill No. 12 of 2005

**THE HIMACHAL PRADESH TAX ON PROFESSIONS, TRADES,
CALLINGS AND EMPLOYMENTS BILL, 2005.**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

*to provide for the levy and collection of a tax on Professions, Trades,
Callings and Employments in the State of Himachal Pradesh.*

Be it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh
in the Fifty-sixth Year of the Republic of India, as follows:—

CHAPTER-I

PRELIMINARY

व
प्र
Short title
and
commence-
ment.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2005.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

- (a) “**Act**” means “the Himachal Pradesh Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2005”;
- (b) “**Assessing Authority**” means any person appointed by the State Government under sub-section (2) of section 3 to make any assessment under this Act;
- (c) “**Calling**” includes usual occupation, vocation, business or trade of a person;
- (d) “**Commissioner**” means the Commissioner appointed under sub-section (1) of section 3;

नियं
भार
पुरः

1 of 1956

- (e) **"Company, Director and Share holder"** shall have the meanings respectively assigned to them in the Companies Act, 1956;
- (f) **"Deputy Excise and Taxation Commissioner"** means the Deputy Excise and Taxation Commissioner, appointed under sub-section (1) of section 3 of this Act, to assist the Commissioner and shall also include the Joint/ Additional Excise and Taxation Commissioner;
- (g) **"employee"** includes a person employed on salary or wages—
 - (i) in the service of the Central Government or any State Government to whom the salary is paid either from the Consolidated Fund of India or of a State;
 - (ii) in the service of a body, whether incorporated or not, which is owned or controlled by the Central Government or any State Government where the body operates in any part of the State, even though its headquarters may be situated outside the State;
 - (iii) in any employment of any employer, not covered under sub-clauses (i) and (ii);
- (h) **"employer"** in relation to an employee earning any salary or wages on regular basis under him, includes a person or an officer responsible for disbursement of such salary or wages, as well as the manager or agent of the employer;
- (i) **"engaged"** in relation to any profession, trade, calling or employment means a person occupied, fully or otherwise, in such profession, trade, calling or employment, whether any pecuniary benefit or benefit of any other nature whatsoever, actually accrues or not to such person;
- (j) **"Government or State Government"** means the Government of Himachal Pradesh;

- (k) **"month"** means a month, reckoned according to the Gregorian Calendar, or part thereof;
- (l) **"person"** means any individual or association or body of individuals and includes a Hindu undivided family or joint family, a firm, a company whether incorporated or not, a co-operative society, a trust, a club, an institution, an agency, a corporation, a local authority and a Department of the Central or the State Governments, engaged actively or otherwise in any profession, trade, calling or employment in the State of Himachal Pradesh, but does not include any person who earns wages on a casual basis.
- (m) **"prescribed"** means prescribed by the rules made under this Act;
- (n) **"salary or wages"** means pay or wages, dearness allowance, and all other remuneration received by any assessee on regular basis whether payable in cash or in kind and perquisites and profits received in lieu of salary as defined in section 17 of the Income Tax Act, 1961, but does not include bonus (in any form or on any account) or gratuity;
- (o) **"Schedule"** means Schedule appended to this Act;
- (p) **"State"** means the State of Himachal Pradesh;
- (q) **"tax"** means the tax on professions, trades, callings and employments levied under section 4 of this Act;
- (r) **"Trade"** means any business carried on with a motive of earning profit, whether or not profit accrues from it; and
- (s) **"year"** means the financial year.

CHAPTER-II

TAXING AUTHORITIES

3. (1) For carrying out the purposes of this Act, the State Government may, by notification, appoint a person to be the

Taxing
Authorities

नियो
भारत
पुरः

क
प्र

43 of 1961

भ

Commissioner and such other persons with such designations as it thinks fit.

(2) The State Government may, by notification, appoint as many Assessing Authorities as it may think fit.

(3) The Commissioner and other persons appointed under sub-section (1) shall perform such functions and duties as may be required by or under this Act or as may be conferred, by the State Government, by notification.

(4) The jurisdiction of the Commissioner and other officers posted at the State headquarters shall extend to the whole of the State of Himachal Pradesh, and the jurisdiction of other officers or officials shall, unless the State Government otherwise directs, by notification, extend to the districts or the areas of the districts for which they are for the time being posted.

CHAPTER-III

INCIDENCE, LEVY, COLLECTION AND EXEMPTION OF TAX

4. (1) There shall be levied and collected a tax on professions, trades, callings and employments at such rates not exceeding rupees two thousand five hundred per annum per person. Levy of tax.

(2) Every person engaged in any profession, trade, calling or employment in the State and falling under any of the classes specified in column (2) of the Schedule-I, shall be liable to pay the tax levied under sub-section (1) at the rate specified in the corresponding entry in column (3) thereof.

5. The tax payable under this Act by any person shall be deducted by his employer from the salary or wage payable to such person, before such salary or wage is paid to him, and shall, irrespective of whether such deduction has been made or not, be liable to pay tax on behalf of such person: Employers liability to deduct and pay tax on behalf of employees.

Provided that the employer shall discharge the liability in the manner prescribed:

Provided further that where any person earning a salary or wage is simultaneously engaged in employment of more than one employer, and if such person furnishes to his employer or employers a certificate

in the prescribed form to the effect that he shall get enrolled under this Act, such employer or employers shall not deduct the tax from his salary or wage payable to him and such employer or employers, as the case may be, shall not be liable to pay tax on his behalf.

Exemption
from tax and
amendment
of
Schedules.

6. (1) No tax shall be payable by the persons specified in the second column of the Schedule-II.

(2) The State Government may, by notification, add to or delete or otherwise amend the Schedules-I and II, and thereupon, the Schedules shall be deemed to have been amended accordingly.

CHAPTER-IV REGISTRATION AND ENROLMENT

Registration
and
enrolment.

7. (1) Every employer, not being an officer of the Central Government, or any State Government or the Government of any Union Territory liable to pay tax under this Act, shall obtain a certificate of registration from the Assessing Authority in the prescribed manner.

(2) Every person, liable to pay tax under this Act, other than a person earning salary or wage, in respect of whom the tax is payable by his employer, shall obtain a certificate of enrolment from the Assessing Authority in the manner prescribed.

(3) Every employer or person required to obtain a certificate of registration or enrolment, shall, within thirty days from the date of commencement of this Act, or, if he was not engaged in any profession, trade, calling or employment on that date, within thirty days of his becoming liable to pay tax, or, in respect of a person referred to in sub-section (2), within thirty days of his becoming liable to pay tax at a rate higher or lower than the one mentioned in his certificate of enrolment, apply for a certificate of registration or enrolment or a revised certificate or enrolment, as the case may be, to the Assessing Authority, in the prescribed form, and such Authority shall, after making such inquiry as may be necessary, within thirty days of the receipt of the application, grant him such certificate:

Provided that where on account of revision of rate of tax, the person liable to pay tax is required to pay tax at a rate higher or lower than the one mentioned in the certificate of enrolment, the rate of tax mentioned in such certificate shall be deemed to have been revised accordingly on the date of such revision of rate of tax as aforesaid; and

pending application the person applying for a revised certificate or enrolment shall, notwithstanding anything contained in this Act, be liable to pay tax at such revised rate.

(4) The Assessing Authority shall mention in every certificate of enrolment the amount of tax payable by the holder in accordance with the notified rates, and the date by which it shall be paid; and such certificate shall, subject to the provisions of the proviso to sub-section (3) serve as a notice of demand for the purposes of recovery.

(5) Where an employer or a person liable to registration or enrolment has wilfully failed to apply for certificate of registration or enrolment, as the case may be, within the required time, the Assessing Authority may, after giving him a reasonable opportunity of being heard, impose—

- (i) in the case of an employer, a penalty not exceeding rupees ten for each day of delay but not exceeding rupees two thousand; and
- (ii) in the case of other, a penalty not exceeding rupees ten per day but not exceeding rupees one thousand in any one case.

(6) Where an employer or a person liable to registration or enrolment has wilfully furnished false information in any application submitted under this section, the Assessing Authority may, after giving him a reasonable opportunity of being heard, impose upon him a penalty not exceeding rupees one thousand.

CHAPTER-V

PAYMENT OF TAX, RETURNS, ASSESSMENT, RECOVERY AND REFUND OF TAX

8. The tax payable under this Act shall be paid in the manner prescribed at such intervals, as may be prescribed. Payment of tax.

9. (1) Every employer registered under this Act, shall furnish to the Assessing Authority, a return in such form, for such periods and by such dates as may be prescribed. Filing of returns.

(2) Every return furnished under sub-section (1) shall be accompanied by a treasury challan in proof of payment of full amount

of tax due according to such return, and a return without such proof of payment of tax shall not be deemed to have been duly furnished.

(3) Where an employer has without reasonable cause failed to furnish such return within the required time, the prescribed authority, after giving him a reasonable opportunity of being heard, may impose upon him a penalty not exceeding rupees ten for each day of delay but not exceeding in the aggregate fifty percent of the tax liability.

Assessment. 10. (1) If the Assessing Authority is satisfied that the return furnished by an employer is correct and complete, it shall be deemed to have been accepted:

Provided that on random basis the Commissioner may require checking of returns for the purpose of this section upto a limit as may be notified.

(2) (a) If the Assessing Authority is satisfied that the return duly filed is not correct or not complete, he shall serve upon the employer a notice requiring him, on a date specified in the notice, to attend in person, or through an authorised representative, and to produce accounts and papers in support of the return.

(b) The Assessing Authority shall, after examination of accounts and papers, assess the amount of tax payable by the employer.

(c) If the employer fails to comply with the terms of the notice, or if in the opinion of the Assessing Authority, the accounts and papers are not correct, or not complete or not reliable, such authority shall, after such inquiry as he deems fit, or otherwise, assess the tax due, to the best of his judgement.

(3) The amount of tax due from any employer shall be assessed separately for each year or part thereof during which he was liable to pay tax.

(4) If an employer has failed to get himself registered, or being registered has failed to furnish any return, or has escaped assessment, the Assessing Authority shall, after giving the employer a reasonable opportunity of being heard and after holding such inquiry as he deems fit, or otherwise, pass an order assessing the amount of tax due, to the best of his judgement.

(5) The amount of tax so assessed shall be paid within thirty days from the date of receipt of the notice of demand from the Assessing Authority.

(6) No order under this section shall be passed after expiry of two years from the close of the year in respect of or part of which the assessment is made:

Provided that if proceedings are stayed by the Appellate Authority or by the competent court, as the case may be, the period of stay shall be excluded in computing the said period of two years:

Provided further that where an assessment order is passed in consequence of or to give effect to any order of an Appellate Authority or a competent court, it shall be completed within a year of the communication of such order to the Assessing Authority.

11. (1) If an assessee, not being an officer of the State Government or the Central Government, or the Government of a Union Territory, does not deduct the tax at the time of payment of salary or wages or after deducting, fails to pay the tax as required by or under this Act, he shall—

Consequences of failure to deduct or to pay tax.

- (a) be deemed to be an assessee in default in respect of the tax; and
- (b) be liable to pay such interest at the rate of one percentum per month on the amount of tax due for each month or part thereof for the period for which the tax remains unpaid.

(2) If an enrolled person fails to pay the tax as required by or under this Act, he shall be liable to pay interest at the rate and in the manner provided under sub-section (1).

12. (1) If an assessee fails, without reasonable cause to make payment of any amount of tax within the time specified in the notice of demand, the Assessing Authority may, after giving him a reasonable opportunity of making his representation, impose upon him a penalty which shall not be less than fifteen percentum but not exceeding twenty five percentum of the amount of tax due.

Penalty for non-payment of tax.

Recovery
of tax.

13. The arrears of tax, penalty, interest or any other amount remaining unpaid after demand notice under this Act, shall be recoverable as an arrear of land revenue.

Liability
under this
Act to be
the first
charge.

14. Notwithstanding anything to the contrary contained in any law for the time being in force, any amount of tax and any other sum payable by any person under this Act, shall be first charge on the property of such person.

Special
mode of
recovery.

15. Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, or contract to the contrary, the Assessing Authority may, at any time, by notice in writing, a copy of which shall be forwarded to the assessee at his last known address, require—

(a) any person from whom any amount of money is due, or may become due, to an assessee on whom notice of demand has been served under this Act,

or

(b) any person who holds or may, subsequently, hold money for or on account of such assessee,

to pay to the Assessing Authority, either forthwith upon money becoming due or being held within the time specified in the notice but not before the money becomes due or is held as aforesaid so much of the money as is sufficient to pay the amount of arrears of tax, penalty and interest under this Act, or the whole of the money when it is equal to or less than that amount.

Refund.

16. The Assessing Authority shall refund to a person the amount of tax, penalty, interest and fees, if any, paid by such person in excess of the amount due from him, and the refund may be made, in the manner prescribed, either by cash payment or, at the option of the person, by deduction of such excess from the amount of tax, penalty, interest and fee due in respect of any other period:

Provided that the Assessing Authority shall first apply such excess towards the recovery of any amount due in respect of which a notice under sub-section (5) of section 10 has been served, and shall then refund the balance, if any.

Appointment
of
collecting
agents.

17. The State Government may, by notification, appoint, for carrying out the purposes of this Act, any officer of the State Government, or local authority, as its collecting agent, who shall be

responsible for the collection of the tax under this Act, from such assesseees as the State Government may, by notification, specify, and thereupon, such collecting agent shall perform the functions assigned to him for the purpose.

CHAPTER-VI APPEAL AND REVISION

18. (1) An appeal from every original order passed by the Assessing Authority shall lie to the Deputy Excise and Taxation Commissioner. Appeal.

(2) An order passed in appeal by the Deputy Excise and Taxation Commissioner shall be further appealable to the Commissioner.

(3) No appeal shall be entertained after the expiry of period of sixty days from the date of the communication of the order appealed against, or such longer period as the Appellate Authority may allow, for reasons to be recorded in writing.

(4) No appeal under sub-section (1) or (2) shall be entertained by an Appellate Authority unless such appeal is accompanied by satisfactory proof of the payment of the tax (including interest payable) or of the penalty, if any, imposed or both, as the case may be:

Provided that if such authority is satisfied that the assessee is unable to pay the tax (including interest payable) assessed or the penalty, if any, imposed or both, he may, for reasons to be recorded in writing, entertain an appeal without the tax (including interest payable) or penalty or both having been paid in full or after part payment of such tax (including interest payable) or penalty or both.

(5) Subject to such rules of procedure as may be prescribed, an Appellate Authority may pass such order on appeal as it deems just and proper.

19. (1) The Commissioner may, of his own motion, call for and examine the record of the proceedings which are pending before, or have been disposed of by, any Assessing Authority, or as the case may be, the Appellate Authority for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of such proceedings or order made therein and, on finding the proceedings or the orders prejudicial to the interest of revenue, may pass such order in relation thereto, as he may think fit. Revision by
the
Commissioner.

(2) No order shall be passed under sub-section (1), which adversely affects any person, unless such person has been given a reasonable opportunity of being heard.

Revision to
the High
Court.

20. (1) Any person or authority aggrieved by an order passed under sub-section (2) of section 18 or under section 19, may, within ninety days from the date of service of such order, apply to the High Court of Himachal Pradesh for revision of such order, if it involves a question of law arising out of erroneous decision of law or failure to decide a question of law.

(2) The High Court shall after hearing the parties to the revision, decide the question of law stated to it or formulated by it, and shall, thereupon, pass such order as is necessary to decide the question of law.

CHAPTER-VII ACCOUNTS

Maintenance
of accounts
by the
employer or
a person.

21. (1) If the Commissioner is satisfied that the books of accounts and other documents maintained by a particular class of employers in the normal course of their business are not adequate for verification of the returns furnished by such employer, he may direct him in writing to maintain the books of accounts and other documents in the manner as may be prescribed, and thereupon such employer shall maintain such books of accounts or other documents accordingly.

(2) Where an employer wilfully fails to maintain the books of accounts or other documents as directed under sub-section (1), the Assessing Authority may, after giving him a reasonable opportunity of being heard, impose a penalty not exceeding rupees fifty for each day of such default subject to a maximum of rupees one thousand.

CHAPTER-VI OFFENCES, PENALTIES AND COMPOSITION OF OFFENCES

Offences
and
penalties.

22. Any person or employer who, without sufficient cause, fails to comply with any of the provisions of this Act or the rules made thereunder, the Assessing Authority may direct that such person or employer shall pay by way of penalty a sum not exceeding rupees one thousand and when the offence is a continuing one with a penalty not exceeding rupees twenty five per day during the period of the continuance of the offence.

Offences by
companies.

23. (1) Where an offence under this Act has been committed by a company, every person who, at the time when the offence was

committed, was incharge of and was responsible to the company for the conduct of the business of the company, such person and the company, shall both jointly and severally be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to penalty as provided for in the Act:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any penalty, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where any offence under this Act has been committed by a company, and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to penalty as provided for in the Act.

Explanation.—For the purposes of this section “company” means any body corporate and includes a firm or other association of individuals; and “director” in relation to a firm means a partner in the firm.

24. (1) Subject to such conditions as may be prescribed, the Assessing Authority may, either before or after the commencement of proceedings under this Act, may compound any offence on payment of an amount which shall not be less than twenty five per centum but which shall not exceed fifty per centum of the maximum penalty provided under the Act. Compounding of offences.

(2) On composition of offence under sub-section (1), no further proceedings shall be taken against the person in respect of the same offence.

CHAPTER-IX MISCELLANEOUS

25. All authorities under this Act shall, for the purposes of this Act, have the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 when trying a suit, in respect of enforcing the attendance of and examining any person on oath or affirmation or for compelling the production of any document. Power to enforce attendance and evidence.

26. No suit shall lie in any civil court to set aside or modify any assessment made or order passed under this Act. Bar of certain proceedings.

Indemnity.

27. No suit, prosecution, or other legal proceedings shall lie against any authority under this Act or against any employer for anything done or intended to be done in good faith under this Act or the rules made thereunder.

Delegation of powers.

28. Subject to such restrictions and conditions, as may be prescribed, the Commissioner may, by order in writing, delegate any of his powers under this Act to an officer not below the rank of Additional Excise and Taxation Commissioner posted at the State headquarters.

Local authorities not to levy profession tax.

29. (1) Notwithstanding anything in any enactment governing the constitution or establishment of a local authority, no local authority shall, on or after the commencement of this Act, levy tax on professions, trades, callings or employments.

(2) Notwithstanding anything in any law for the time being in force, no cess shall be levied on tax on professions, trades, callings or employments under any such law and the provisions in such law authorising such levy and collection shall, on and from the date of commencement of this Act, stand repealed.

Transitional provisions.

30. Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, any authority exercising any power under the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 and any rule relating to deduction of tax and its payment into the Government treasury, filing of returns and challan, in so far as these are applicable for the purposes of levy and collection of value added tax, shall *mutatis mutandis* apply for the purposes of deduction and payment of tax under this Act, until the rules are made under this Act or the expiry of six months from the date of commencement of this Act, whichever is earlier.

12 of 2005

Power to make rules.

31. (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules in consistent with this Act, for securing the levy and collection of tax and generally for carrying out the purposes of this Act.

(2) Every rules made under this Act shall immediately after it is made, be laid before the Legislative Assembly of the State if it is in session and if it is not in session, in the session immediately following for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions and if, before the expiration of the session in which it is so laid or the session immediately following, the Legislative Assembly agrees in making any modification in the rule or in the annulment of the rule, the rule shall, from the date on which the modification or annulment is notified, have effect only in such modified form or shall stand annulled, as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

SCHEDULE -I
(See sections 4 and 6)

Sl. No.	Classes of Assesseees	Rate of Tax
1	2	3
1.	Salary and wage earners having monthly salaries or wages—	
	(i) upto Rs. 4000/- per month	Nil
	(ii) salary from Rs. 4001/- to Rs. 10000/-	Rs.100/- per month
	(iii) salary from Rs. 10001/- to Rs. 15000/-	Rs.150/- per month
	(iv) salary above Rs.15001/-	Rs. 200/- per month
2.	(a) Legal Practitioners including Solicitors and Notaries Public, Technical and Professional Consultants, Chartered Accountants and Architects with standing / practice in the profession —	
	(i) upto 5 years	Nil
	(ii) between 5 to 10 years	Rs. 50/- per month
	(iii) between 10 to 15 years	Rs. 150/- per month
	(iv) above 15 years	Rs. 200/- per month
	(b) Deed/ document writers	Rs. 100/- Per month
3.	(a) Chief Agent, Principal Agent, Special Agent, Insurance Agent, Surveyors or Loss Assessors registered or licensed under the Insurance Act, 1938 (Central Act IV of 1938)	Rs. 200/- per month
	(b) Postal Agents under the National Small Saving Schemes (earning more than Rs. 48000/- per annum)	Rs. 100/- per month
4.	Members of the Stock Exchanges recognised under Security Contracts (Regulation) Act, 1956, Auctioneers and Commission Agents.	Rs. 200/- per month
5.	(a) Estate Agents or Brokers	Rs. 200/- per month
	(b) Public Works Department contractors (registered as per the guidelines issued by the	

1

2

3

Government from time to time and actively
executing works contract) —

- | | | |
|-------|---|---------------------|
| (i) | Class 'A' contractors | Rs.200/- per month |
| (ii) | Class 'B' contractors | Rs.200- per month |
| (iii) | Class 'C' contractors | Rs.150/- per month |
| (iv) | Class 'D' contractors | Rs. 50/- per month |
| (c) | Forests contractors | Rs.150/- per month |
| (d) | any other contractor | Rs.100/- per month |
| 6. | Directors (other than those nominated by the Government) of Companies Registered under the Companies Act, 1956. | Rs.200/- per month |
| 7. | Dealer registered or liable to be registered under the Himachal Pradesh General Sales Tax Act, 1968 (24 of 1968), the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (12 of 2005) and the Central Sales Tax Act, 1956 (74 of 1956), Khadi and Village Industrial Units, having annual turnover— | |
| (i) | upto Rs. 4 lakhs | Nil |
| (ii) | between Rs. 4 lakhs and 10 lakhs | Rs.100/- per month |
| (iii) | between 10 lakhs and 25 lakhs | Rs.150/- per month |
| (iv) | above 25 lakhs | Rs.200/- per month |
| 8. | Occupier of a factory as defined under the Factories Act, 1948 (63 of 1948) who is not covered by item No. 7. | Rs. 200/- per month |
| 9. | Owner or lessee of petrol/ diesel/ aviation turbine fuel filling stations and service stations, garages and workshops of automobiles. | Rs.200/- per month |
| 10. | Owner or lessee of Rice Mill, Oil Mill, Spinning Mill, Paper Mill, Dall Mill, Powerloom, Mini Steel Plant, Rolling Mill, Khandasari Sugar Factory, Sugar Factory Foundry, Tannery, Stone Crusher, Bottling Unit, Distillery, Tile Factory, Biscuit Factory, Chemical and Pharmaceutical Lab, Printing Press (with power), Fruit Canning Unit. | Rs. 200/- per month |
| 11. | Employer of establishment as defined under the Himachal Pradesh Shops and Commercial Establishments Act, 1969 (who are dealers not | |

1

2

3

covered by item (7) who have —

	(i) no employee	Nil
	(ii) not more than 5 employees	Rs. 50/- per month
	(iii) more than 5 employees but not more than 10 employees	Rs. 100/- per month
	(iv) more than 10 employees but not more than 20 employees	Rs. 150/- per month
	(v) more than 20 employees	Rs. 200/- per month
12.	Owner or lessee of Nursing Home or Hospital other than the one run by the State Government or the Central Government.	Rs. 200/- per month
13.	(b) Owner of residential Hotels or Lodging Houses having not less than 10 rooms.	Rs. 200/- per month
	(c) Guest houses and serais	Rs. 100/- per month
	(d) (i) Owner of theatre	Rs. 200/- per month
	(ii) Owner of touring talkie	Rs. 200/- per month
	(iii) Owner of Video parlor:	
	(a) urban areas	Rs. 100/- per month
	(b) rural areas	Rs. 50/- per month
	(iv) Cable TV operator:	
	(a) in Municipal areas	Rs. 100/- per month
	(b) in rural areas	Rs. 50/- per month
14.	Banking company as defined in the Banking Regulations Act, 1949.	Rs. 200/- per month
15.	All companies registered under the Companies Act, 1956 engaged in a profession, trade or calling.	Rs. 200/- per month
16.	All medical practitioners including dentists, radiologists, pathologists and persons engaged in professions or calling of paramedical nature.	Rs. 200/- per month
17.	Film Distributors, all type of travel agents and advertising firms/ agencies.	Rs. 200/- per month
18.	Journalists:	
	(a) State level	Rs. 200/- per month
	(b) District level	Rs. 100/- per month

1	2	3
	(c) Sub-divisional level	Rs. 50/- per month
19.	(a) Persons owning Photocopying machines for job works:	
	(i) in urban areas	Rs. 100/- per month
	(ii) in rural areas	Rs. 50/- per month
	(b) Persons providing services of coaching (other than sports) typing, printing, lamination etc.	Rs. 200/- per month
20.	Educational Institutions, Tutorial Colleges, Institutes (other than those owned by the State Government or the Central Government)	Rs. 200/- per month
21.	Property Developers including Land Developers and Building/ Flat Developers	Rs. 200/- per month
22.	Persons owning/running —	
	(a) Computer Institutes selling time	Rs. 100/- per month
	(b) Computer Training Institutes or E-café	Rs. 200/- per month
	(c) Driving Institutes/Technical Training Institutes	Rs. 100/- per month
	(d) Video Cassette Libraries	Rs. 200/- per month
	(e) Indoor sports or health facilities in Municipal areas.	Rs. 200/- per month
23.	Persons owning Marriage Halls and providing these on rent or agencies providing sound, lighting, furniture, tent houses, shamiana etc. on payment for marriages/ functions.	Rs. 200/- per month
24.	(a) Transport companies and transport contractors including forwarding and clearing agent.	Rs. 200/- per month
	(b) Bankers who are financing the trade against hundies or other securities by way of short-term advance on interest.	Rs. 200/- per month
25.	(a) Authorized assistants recognized by stock exchange	Rs. 200/- per month
	(b) Persons operating courier service	Rs. 200/- per month
26.	Persons running—	
	(a) ISD, STD booths in urban areas	Rs. 100/- per month
	(b) Cold storage	Rs. 200/- per month
	(c) Motor vehicle parking or more than 20 vehicles in urban areas.	Rs. 200/- per month

SCHEDULE -II
(See section 6)

Sl. No.	Classes of Assesseees
▼ 1	2
1.	Daily waged earners.
2.	Employees hired by State Government on contract basis.
3.	Co-operative Societies.
4.	Small and petty dealers with turnover upto Rs. 4 lakhs.
5.	Agriculturalist including orchardists; support service providers in villages like carpenters, blacksmiths, rural artisans, barber, nai, dhobi, gharati, teli, kasai etc. (except beauty parlor and saloons in urban areas).
6.	Freedom Fighters.
7.	Pensioners.
8.	Military, Navy and Air Force personnel including Central Paramilitary personnel.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

As the State Government is required to finance the expanded social security system for the benefit of the poor, therefore, it has been decided to levy tax on professions, trades, callings and employments in the State, by enacting necessary legislation.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

RANGILA RAM RAO,
Minister-Incharge.

SHIMLA:

The2005.

FINANCIAL MEMORANDUM

Clause 4 of the Bill proposes to levy a tax on professions, trades, callings and employments on the classes of Assesseees specified under column (2) of Schedule-I at the rates specified in the corresponding entry in column (3) thereof. The provisions of the Bill, when enacted, are estimated to yield about 45 crores rupees per annum to the State exchequer. As the provisions of the Bill after being enacted, are to be enforced through the existing Government machinery, no additional expenditure will be involved.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 31 of the Bill seeks to empower the State Government to make rules for carrying out the purposes of the Bill. The proposed delegation of powers are essential and normal in character.

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

(File No. EXN-F(6)-2/2005)

The Governor, Himachal Pradesh, after having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Bill, 2005, recommends, under articles 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the Legislative Assembly.

**THE HIMACHAL PRADESH TAX ON PROFESSIONS, TRADES, CALLINGS AND
EMPLOYMENTS BILL, 2005**

A

BILL

*to provide for the levy and collection of a tax on Professions, Trades, Callings and
Employments in the State of Himachal Pradesh.*

RANGILA RAM RAO,
Minister-in-Charge.

SURINDER SINGH THAKUR,
Secretary (Law).

SHIMLA:

The2005.